टैक्स 23% बढ़कर 8 .11 लाख करोड़

10 अगस्त तक सरकार के खजाने में बढ़ी टैक्स की आवक, गैर-कॉरपोरेट कर संग्रह में सबसे ज्यादा उछाल

नई दिल्ली, 12 अगस्त चालू वित्त वर्ष 2026-27 में केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर संग्रह में मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है. आयकर विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, 1 अप्रैल से 10 अगस्त 2026 तक देश का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 23.09 प्रतिशत बढ़कर 8.11 लाख करोड़ रुपए हो गया.

पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा करीब 6.59 लाख करोड़ रुपए था. यानी एक साल में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में लगभग 1.52 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है.

आंकड़ों के अनुसार, रिफंड को घटाने से पहले कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 9.55 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के 7.97 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 19.75 प्रतिशत अधिक है. इस अवधि में करदाताओं को 1.43 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया. रिफंड की राशि पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 3.79 प्रतिशत अधिक रही. इसके बावजूद सरकार का शुद्ध कर संग्रह तेजी से बढ़ा है.

कर संग्रह में सबसे बड़ा योगदान गैर-कॉरपोरेट करों का रहा. इसमें व्यक्तिगत आयकर समेत व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ), फर्मों और अन्य गैर-कॉरपोरेट संस्थाओं से मिलने वाला कर शामिल है. आंकड़ों के मुताबिक, शुद्ध गैर-कॉरपोरेट कर संग्रह पिछले साल के 4.11 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर इस साल 5.07 लाख करोड़ रुपए हो गया.

> नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीजीए) के आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा करीब 3.1 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पूरे वित्त वर्ष के बजट अनुमान का 18.2 प्रतिशत है. पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह करीब 2.8 लाख करोड़ रुपए था. ऐसे में प्रत्यक्ष कर संग्रह में मजबूत वृद्धि सरकार की राजकोषीय स्थिति को संभालने में अहम भूमिका निभा सकती है.

सीतारमण जयपुर के दो दिवसीय दौरे पर

नयी दिल्ली, 12 अगस्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से दो दिन के लिए जयपुर में रहेंगी जहां वहां ब्रिक्स समूह के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठकों में शामिल होने के अलावा कुछ अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगी.

वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि ये बैठकें बुधवार को सुबह नौ बजे रामबाग पैलेस में शुरू होंगी और दिन भर चलेंगी तथा गुरुवार को लगभग 12:30 बजे सम्पन्न होंगी. सीतारण गुरुवार को जयपुर में ही राजस्थान इंटररनेशनल सेंटर में राजस्थान युवा सम्मेलन में भाग लेंगी और युवाओं तथा स्टार्टअप इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगी.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता की गलती पर बैंक नहीं बचेंगे

कृत्रिम बुद्धिमता के फैसलों में मानवीय निगरानी जरूरी

तकनीक की आड़ में जिम्मेदारी से नहीं बच पाएंगे बैंक

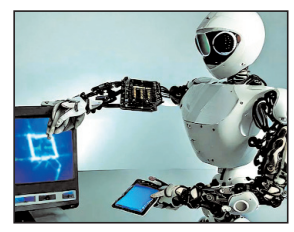

नई दिल्ली, 12 अगस्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के बढ़ते इस्तेमाल के बीच भारतीय रिजर्व बैंकने बैंकों को स्पष्ट संदेश दिया है कि तकनीक के पीछे छिपकर अपनी जिम्मेदारी से बचना संभव नहीं होगा.

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि बैंक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियों का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन इनके संचालन और फैसलों में मानवीय निगरानी को अनिवार्य हिस्सा बनाएं. अगर किसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली की वजह से कोई गलत निर्णय होता है या ग्राहक को नुकसान पहुंचता है तो बैंक यह दलील नहीं दे सकेंगे कि गलती तकनीक की थी. ऐसी दलील को नियामक, ग्राहक और बैंकिंग व्यवस्था किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं करेंगे.मुंबई में आयोजित सालाना फाइबैक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक बड़ी क्षमता के रूप में सामने आ रही है. इससे ग्राहकों को तेज, बेहतर और अधिक सुविधाजनक सेवाएं दी जा सकती हैं. ऋण प्रक्रिया, जोखिम पहचान, धोखाधड़ी रोकने और ग्राहक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका लगातार बढ़ रही है.

> केंद्रीय बैंक का मानना है कि तकनीक का विकास जरूरी है, लेकिन इसके साथ पारदर्शिता, सुरक्षा और जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. बैंकों के लिए अब चुनौती यह होगी कि वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल बढ़ाएं, लेकिन इसके साथ मजबूत निगरानी व्यवस्था भी विकसित करें. उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीक से लिए गए फैसले ग्राहकों के हितों के अनुरूप हों और किसी भी गलती की स्थिति में जिम्मेदारी तय की जा सके. आरबीआई गवर्नर के संदेश से साफ है कि आने वाले समय में बैंकिंग क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल और बढ़ेगा, लेकिन इसके संचालन के नियम भी उतने ही सख्त होंगे.

वस्तु निर्यात दूसरी तिमाही में 131 अरब डॉलर पार

नयी दिल्ली, 12 अगस्त भारत के निर्यात-आयात बैंक (एग्जिम बैंक) ने अनुमान लगाया है कि देश का कुल वस्तु निर्यात चालू वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में 131 अरब डॉलर के पार पहुंच जायेगा.

एग्जिम बैंक ने बुधवार को कहा है कि दूसरी तिमाही में वस्तु निर्यात 17.6 प्रतिशत बढ़कर 131.2 अरब डॉलर रहने की संभावना है. इस अवधि में गैर-तेल निर्यात में 20.3 प्रतिशत और गैर-तेल तथा गैर-रत्न एवं आभूषण निर्यात में 20.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है. गैर-तेल निर्यात 113.8 प्रतिशत और गैर-तेल तथा गैर-रत्न एवं आभूषण निर्यात 105.8 अरब डॉलर रहने की संभावना जतायी गयी है.

कुल वस्तु निर्यात, गैर-तेल निर्यात तथा गैर-तेल एवं गैर-रत्न-आभूषण निर्यात की वृद्धि का अनुमान एग्जिम बैंक द्वारा प्रत्येक तिमाही में जारी किया जाता है. ये अनुमान संबंधित तिमाही के लिए मई, अगस्त, नवंबर और फरवरी के पहले पखवाड़े में जारी किये जाते हैं.

कहा गया है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद निर्यात में यह बढ़ोतरी निर्यात बाजारों के भौगोलिक विविधीकरण में वृद्धि तथा प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों के साथ हाल में किये गये व्यापार समझौतों से उत्पन्न अनुकूल संभावनाओं के कारण संभव होगी.

सेबी से एफएंडओ नुकसान घटा

नई दिल्ली, 12 अगस्त भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के सख्त नियामकीय कदमों का असर अब वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) कारोबार में दिखाई देने लगा है. वित्त वर्ष 2025-26 में इक्विटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में खुदरा निवेशकों का कुल नुकसान 18 प्रतिशत घटकर 91,685 करोड़ रुपए रह गया है. सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में यह जानकारी दी. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में बताया कि नवंबर 2024 से लागू किए गए सेबी के विभिन्न सुधारों के बाद एफएंडओ बाजार में व्यक्तिगत निवेशकों की भागीदारी और कारोबार की गतिविधियों में कमी आई है.

रेप्को को 114 करोड़ रुपये का मुनाफा

n ऋण बुक में 8 .9% की सालाना वृद्धि दर्ज n जीएनपीए घटकर 2 .7% पर आया

चेन्नई, 12 अगस्त रेप्को होम फाइनेंस लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2026) के वित्तीय परिणाम जारी किए हैं। कंपनी के निदेशक मंडल ने भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अनुसार 30 जून 2026 को समाप्त तिमाही के परिणामों को मंजूरी दी।

कंपनी ने इस अवधि में 114 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में शुद्ध लाभ 108 करोड़ रुपये था।कंपनी की ऋण बुक में भी मजबूत वृद्धि दर्ज की गई।30 जून 2026 तक कंपनी का कुल ऋण पोर्टफोलियो 15,990 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले 14,690 करोड़ रुपये था। इस तरह ऋण बुक में 8.9 प्रतिशत की सालाना वृद्धि हुई। मार्च 2026 के अंत में कंपनी का प्रबंधन अधीन परिसंपत्ति (एयूएम) 15,880 करोड़ रुपये था।पहली तिमाही में कंपनी ने 938 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए, जबकि पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह आंकड़ा 907 करोड़ रुपये था। वहीं, ऋण वितरण 843 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में 829 करोड़ रुपये था।

कंपनी की कुल आय जून तिमाही में 468 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के 441 करोड़ रुपये की तुलना में 6.1 प्रतिशत अधिक है। शुद्ध ब्याज आय भी बढ़कर 216 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले साल यह 196 करोड़ रुपये थी। इसमें 10.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

> कंपनी ने बताया कि 30 जून 2026 तक कुल ऋण बुक में गैर-वेतनभोगी वर्ग की हिस्सेदारी 53 .5 प्रतिशत रही, जबकि वेतनभोगी वर्ग की हिस्सेदारी 46 .5 प्रतिशत रही। कुल ऋण में आवास ऋण की हिस्सेदारी 70 .8 प्रतिशत और होम इक्विटी उत्पादों की हिस्सेदारी 29 .2 प्रतिशत रही। कंपनी द्वारा दिए गए सभी ऋण खुदरा ऋण श्रेणी में आते हैंपरिसंपत्ति गुणवत्ता के मोर्चे पर भी सुधार देखने को मिला।

जुलाई में खुदरा महंगाई बढ़कर 4 .45% पहुंची

नई दिल्ली, 12 अगस्त देश में खुदरा महंगाई ने जुलाई में एक बार फिर बढ़त दर्ज की है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2026 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति सालाना आधार पर बढ़कर 4.45 प्रतिशत हो गई. जून में यह दर 4.38 प्रतिशत थी. इस तरह एक महीने में खुदरा महंगाई में 0.07 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई है.

महंगाई में यह बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है, जब भारतीय रिजर्व बैंक का मध्यम अवधि का लक्ष्य 4 प्रतिशत है. हालांकि 4.45 प्रतिशत की दर अभी भी रिजर्व बैंक की 2 से 6 प्रतिशत की सहनशीलता सीमा के भीतर है, लेकिन लगातार दूसरे महीने महंगाई का लक्ष्य से ऊपर रहना नीति-निर्माताओं के लिए चिंता का विषय बन सकता है. जून में भी खुदरा महंगाई 4 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर रही थी.

महंगाई बढ़ने की प्रमुख वजहों में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बनी तेजी को माना जा रहा है. जून में खाद्य मुद्रास्फीति 5.32 प्रतिशत रही थी, जो कुल खुदरा महंगाई की तुलना में काफी अधिक थी. खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर आम परिवारों के मासिक बजट पर पड़ता है.

खासकर सब्जियों, अनाज और अन्य रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों में बढ़ोतरी से घरेलू खर्च बढ़ सकता है. जुलाई की महंगाई दर बाजार के अनुमान के करीब रही.

> लगातार बढ़ती खुदरा महंगाई का असर आने वाले समय में मौद्रिक नीति पर भी दिखाई दे सकता है. रिजर्व बैंक ब्याज दरों पर फैसला लेते समय महंगाई के रुख, खाद्य कीमतों और अर्थव्यवस्था की स्थिति पर नजर रखता है. फिलहाल महंगाई निर्धारित सहनशीलता सीमा में है, लेकिन यदि खाद्य और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तेजी आगे भी जारी रहती है, तो महंगाई के दबाव को नियंत्रित करना चुनौती बन सकता है. उपभोक्ताओं के लिए बढ़ती महंगाई का मतलब रोजमर्रा की खरीदारी पर अधिक खर्च है. वहीं, सरकार के लिए खाद्य आपूर्ति और कीमतों को स्थिर रखना अहम होगा.

इंटर्न से टाटा संस चेयरमैन तक

रतन टाटा के भरोसेमंद सहयोगी ने संभाली कमान, समूह को दी नई रफ्तार

मुंबई, 12 अगस्त टाटा समूह के इतिहास में एक अहम अध्याय अब बदलाव की ओर बढ़ रहा है. टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने अपने मौजूदा कार्यकाल के बाद पद पर आगे बने रहने की इच्छा नहीं जताई है. उनका कार्यकाल फरवरी 2027 में समाप्त हो रहा है और इसके बाद समूह में नए नेतृत्व की प्रक्रिया शुरू होगी.

एन. चंद्रशेखरन की कहानी टाटा समूह के भीतर मेहनत, तकनीकी विशेषज्ञता और नेतृत्व क्षमता की मिसाल मानी जाती है. साल 1987 में उन्होंने टाटा समूह की आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) में एक इंटर्न के रूप में अपना करियर शुरू किया था. धीरे-धीरे अपनी काबिलियत के दम पर वे कंपनी के शीर्ष पद तक पहुंचे और बाद में टीसीएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने.

साल 2017 में उन्हें टाटा संस का चेयरमैन नियुक्त किया गया. यह जिम्मेदारी ऐसे समय मिली थी, जब समूह को रतन टाटा के बाद मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी. चंद्रशेखरन को रतन टाटा का भरोसेमंद सहयोगी माना गया और उन्होंने समूह की कई बड़ी कंपनियों को नई दिशा देने का काम किया.

डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे टूटा

मुंबई, 12 अगस्त शुरुआती कारोबार में बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया करीब 6 पैसे कमजोर होकर 95.42 के स्तर पर पहुंच गया. कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के बीच डॉलर की मांग बढ़ने से रुपये पर दबाव बना. अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया करीब 95.40 के स्तर पर खुला और दिनभर सीमित दायरे में कारोबार करता रहा. बाद में रुपये में कुछ सुधार देखा गया और यह करीब 95.33 के स्तर पर बंद हुआ.

गिरावट के साथ बंद हुआ भारतीय शेयर बाजार

मुंबई, 12 अगस्त भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को गिरावट देखने को मिली. कारोबार के अंत में प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 187.90 अंक टूटकर 77,966.35 अंक पर बंद हुआ.

वहीं, राष्ट्रीय शेयर बाजार का निफ्टी-50 सूचकांक भी 35.75 अंक की गिरावट के साथ 24,435.95 अंक के स्तर पर बंद हुआ. बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया और खरीदारी की गति कमजोर रही. कारोबार के दौरान बाजार पर वैश्विक संकेतों और घरेलू स्तर पर निवेशकों की सतर्कता का असर दिखाई दिया. कई प्रमुख शेयरों में बिकवाली के चलते सेंसेक्स और निफ्टी दबाव में रहे. हालांकि, कुछ क्षेत्रों के शेयरों में खरीदारी से गिरावट सीमित रही.

समाचार विशेष

क्या आरजेडी से दूर हो गए मुस्लिम वोटर?

पटना. बांकीपुर उपचुनाव का एक निष्कर्ष यह भी है कि अब मुस्लिम वोटर प्रशांत किशोर (पीके) के साथ आ गये हैं. मुस्लिम बहुल बूथों पर जन सुराज पार्टी को बंपर वोट मिले हैं. सवाल उठ रहा है क्या मुस्लिम वोटर ने राजद से दामन झटक लिया है. लालू यादव और तेजस्वी यादव की नाक के नीचे राजद की जमानत जब्त हो गयी.

बिहार की राजनीति के लिए यह एक अभूतपूर्व घटना है. मुसलमान अब वोट बैंक बन कर नहीं रहना चाहते. इस बार उन्होंने प्रशांत किशोर पर भरोसा कर विकास के नाम पर वोट दिया है. धर्म से ऊपर उठकर वोट किया है.

पटना के अशोक राजपथ स्थित अंजुमन इस्लामिया हॉल में चार बूथ थे. यह सब्जीबाग के नजदीक है और एक मुस्लिम बहुल इलाका है. अधिकांश वोटर मुस्लिम समुदाय के हैं. यहां के चारो बूथ पर कुल मिलाकर प्रशांत किशोर को 1363 वोट मिले, जबकि राजद को केवल 362 वोट. भाजपा को भी 124 वोट मिले. बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का यह सबसे सघन मुस्लिम इलाका है. यहां के वोटरों ने प्रशांत किशोर के पक्ष में एकतरफा वोट किया. पीके की ईमानदारी और तार्किक बातों ने इन वोटरों पर गहरा असर डाला.

प्रशांत किशोर की अपील का असर प्रशांत किशोर ने कहा था, अब तक आपने जाति-धर्म पर बहुत बार वोट दिये. आपको क्या मिला, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता. आपके वोट से कोई और राज करे और आपका अपना बच्चा बेआसरा रहे? इस बार आप अपने बच्चों का मुंह देख कर वोट कीजिए.

प्रशांत किशोर अब अल्पसंख्यकों में लोकप्रिय

बांकीपुर के नतीजे से यह प्रतीत हो रहा है कि अब प्रशांत किशोर मुसलमानों में लोकप्रिय हो रहे हैं. 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को आबादी के हिसाब से राजनीति में प्रतिनिधित्व देने की बात कही थी. टिकट भी ज्यादा दिये थे. लेकिन उस समय अल्पसंख्यक वोटरों ने उन पर भरोसा नहीं किया था. लेकिन पिछले आठ दस महीने में उन्होंने हकीकत देख ली. दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हार के बाद भी लगातार मेहनत कर रहे थे. नयी राजनीति की बात कर रहे थे. विकास की बात कर रहे थे. अब अल्पसंख्यकों को लगा कि प्रशांत किशोर की नयी राजनीति से जुड़ जाना चाहिए. कई लोगों को अब यह भी लग रहा है देर-सबेर प्रशांत किशोर राजद को पीछे छोड़ कर भाजपा का विकल्प बन सकते हैं.

अगला चुनाव धामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा

धामी खुद किस विधानसभा सीट से मैदान में उतरेंगे, यह तय नहीं

देहरादून. उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चुनावी सीट को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं. भाजपा ने संकेत दे दिए हैं कि अगला विधानसभा चुनाव धामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन धामी खुद किस विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे, यह अभी तय नहीं हुआ है.

राजनीतिक हलकों में चंपावत के साथ-साथ उनके पुराने चुनावी क्षेत्र खटीमा और अब ऊधम सिंह नगर की काशीपुर व रुद्रपुर सीटों को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं.

धामी ने 2022 में खटीमा से चुनाव हारने के बाद चंपावत विधानसभा सीट से उपचुनाव जीता था. तब से वह चंपावत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. इसलिए स्वाभाविक तौर पर चंपावत को उनकी सबसे मजबूत संभावित सीट माना जा रहा है. लेकिन 2027 के लिए अभी तक भाजपा की ओर से यह घोषणा नहीं हुई है कि धामी चंपावत से ही दोबारा चुनाव लड़ेंगे. धामी की राजनीतिक पहचान लंबे समय तक खटीमा से जुड़ी रही है. वह 2012 और 2017 में इसी सीट से विधायक चुने गए थे. 2022 में भी भाजपा ने उन्हें खटीमा से मैदान में उतारा, लेकिन कांग्रेस के भुवन चंद्र कापड़ी से उन्हें हार मिली. इसके बाद चंपावत उपचुनाव के जरिए धामी विधानसभा पहुंचे. इसलिए खटीमा से दोबारा चुनाव लड़ने की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता. हालांकि, 2022 का चुनाव परिणाम उनके सामने सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती भी रखता है.

भाजपा के लिए धामी की सीट क्यों अहम?

2027 में भाजपा के सामने लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटने की चुनौती है. 2022 में पार्टी ने 47 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, जबकि धामी खटीमा से चुनाव हार गए थे. इसके बावजूद पार्टी नेतृत्व ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाए रखा और बाद में चंपावत उपचुनाव से उन्होंने विधानसभा की सदस्यता हासिल की. इस बार स्थिति अलग है. भाजपा ने पहले ही धामी को 2027 के चुनाव का नेतृत्व करने के लिए आगे कर दिया है.

दलित वोट बैंक में सेंध की भाजपा की तैयारी

चंडीगढ़. पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के साथ ही सूबे में राजनीतिक बिसात बिछने लगी है. लंबे समय तक पंजाब के शहरी हिंदू वोटों और अकाली दल के पिछलग्गू बनकर राजनीति करने वाली बीजेपी इस बार फूंटफुट पर बैटिंग करने की पूरी तैयारी कर ली है.

कई दशक तक पंजाब में गठबंधन के छोटे साझेदार के रूप में सीमित रहने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार एक बड़े सियासी बदलाव की तैयारी में है. पार्टी की नजर राज्य की सबसे बड़ी सामाजिक ताकत दलित वोट बैंक पर टिक गई है. बीजेपी हरियाणा मॉडल गैर-जाट और पिछला-दलित समीकरण की सफलता के बाद पंजाब में भी गैर-जट सिख और दलित-हिंदू गठजोड़ का चक्रव्यूह रच रही है. इसका सीधा मकसद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जनाधार को सीधे निशाने पर लेना है.

पंजाब में लगभग 32 से 33 प्रतिशत दलित हैं. जट सिख आबादी लगभग 19 से 21 प्रतिशत है. शहरी गैर-दलित हिंदू लगभग 18 से 20 प्रतिशत हैं. अन्य पिछड़ा वर्ग लगभग 20 से 31 प्रतिशत है. लेकिन पंजाब का दलित समाज एकमुश्त नहीं है, बल्कि यह मुख्य रूप से दो-तीन बड़े धार्मिक और सामाजिक धड़ों में बंटा हुआ है.

रविदासिया समूह का सिख व हिंदू. ये लोग डेरा सचखंड बल्लां से प्रभावित हैं. इनकी आबादी लगभग 13 प्रतिशत है और ये दोआबा क्षेत्र जालंधर और होशियारपुर में रहते हैं. दूसरा, मजहबी सिख मुख्य रूप से सिख धर्म से जुड़े हैं और इनकी संख्या लगभग 10 प्रतिशत के आसपास है. ये मालवा और माझा क्षेत्र में रहते हैं. तीसरा, भंगी हिंदू सिख की आबादी लगभग 3.5 प्रतिशत है. ये पूरे पंजाब के शहरी व ग्रामीण इलाके में रहते हैं. बीजेपी की नजर अब इन वोटरों पर है.

बीजेपी का 'चक्रव्यूह'

बीजेपी ने पंजाब 2027 के लिए तीन-स्तरीय घेराबंदी तैयार की है. पहला, पंजाब के दलित वोट बैंक पर डेरों जैसे डेरा सचखंड बल्लां, डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास का गहरा प्रभाव है. केंद्र सरकार के माध्यम से बीजेपी ने डेरा प्रमुखों के साथ सीधे संपर्क और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे करतारपुर कॉरिडोर, गुरु रविदास महाराज स्थलों का सौंदर्यीकरण को प्राथमिकता दी है. दूसरा, कांग्रेस ने 2021 में चरनजीत सिंह चन्नी को पहला दलित मुख्यमंत्री बनाकर बड़ा दांव खेला था.

विशेष दूसरा खेमा पार्टी पर नियंत्रण बनाने की कोशिश करेगा

अन्नाडीएमके के एक होने की शर्त

चेन्नई. तमिलनाडु में विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद सभी पार्टियों के अंदर किसी न किसी तरह का विवाद और परेशानी चल रही है. कांग्रेस ने डीएमके को छोड़ा तो अन्ना डीएमके में फूट हो गई. उसके आधा दर्जन विधायकों ने इस्तीफा दिया हुआ है.

एक समय तो 20 के करीब विधायक अलग हो गए थे. हालांकि बाद में सब वापस लौटे. फिर भी इन विधायकों का नेतृत्व करने वाले नेताओं ने पार्टी की एकजुटता के लिए एक शर्त रख दी है. शर्त ऐसी है, जिसे स्वीकार करने पर पार्टी के महासचिव ई पलानीस्वामी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

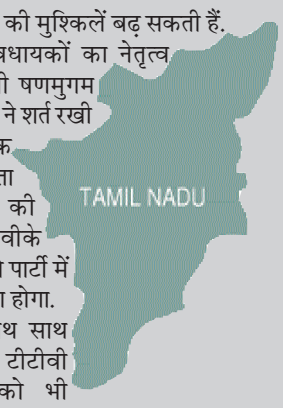

नाराज विधायकों का नेतृत्व कर रहे सीवी षणमुगम और वेलुमनि ने शर्त रखी है कि पार्टी कि दिवंगत नेता जयललिता की सहेली वीके शशिकला को पार्टी में शामिल करना होगा.

उनके साथ साथ उनके भतीजे टीटीवी दिनाकरण को भी पार्टी में लेना होगा. गौरतलब है कि दिनाकरण और शशिकला दोनों ने अलग पार्टी बनाई है.

इन दोनों का एक समय पार्टी में बड़ा असर रहा है और ये पार्टी के थेवर वोट आधार का प्रतिनिधित्व करते हैं. इनके पार्टी में लौटने से पलानीस्वामी की स्थिति कमजोर होगी. इनके साथ मिल कर दूसरा खेमा पार्टी पर नियंत्रण बनाने की कोशिश करेगा.

हालांकि पलानीस्वामी के लिए अच्छी बात यह है कि ओ पनीरसेल्वम को लौटाने की बात नहीं हो रही है. वे चुनाव से पहले डीएमके से जुड़ गए थे.